भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4842

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026 /02 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है)

डिजिटल रुपया और विदेश में डिजिटल भुगतान में वृद्धि

4842. श्री विष्णु दयाल रामः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:

श्री दुलू महतोः

श्री दामोदर अग्रवाल:

श्री प्रवीण पटेल:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री महेश कश्यपः

श्री मुकेश राजपूतः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन के बाद शुरू किए गए डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल रुपये को वैध मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रायोगिक चरणों में प्रगति, प्रयोक्ताओं द्वारा इसे स्वीकार करने और संस्थाओं द्वारा इसके उपयोग में भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में दक्षता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए वैदेशिक प्रायोगिक पहल और बहुपक्षीय सहयोग किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहभागी क्षेत्राधिकार क्या हैं और विदेश से लेन-देन निपटान तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 30 मार्च, 2022 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में आवश्यक संशोधनों को अधिसूचित किया, जिससे 'डिजिटल रुपया' को कानूनी मुद्रा का दर्जा प्रदान किया गया, इस प्रकार, प्रायोगिक चरण शुरू करने में सक्षम बनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने थोक सीबीडीसी के लिए 1 नवंबर, 2022 को डिजिटल रुपया (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-सीबीडीसी) में और खुदरा सीबीडीसी के लिए 1 दिसंबर, 2022 को प्रायोगिक चरण लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में अंतिम लॉन्च पर निर्णय लेने से पहले एक चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्यनीति की दिशा में काम कर रहा है। प्रायोगिक चरण की शुरुआत व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी भुगतान के साथ हुई और बाद में, ऑफलाइन और प्रोग्राम करने योग्य कार्यात्मकताओं का भी परीक्षण किया जा रहा है। कई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं के लिए प्रोग्रामेबिलिटी की विशिष्ट विशेषता का लाभ उठाया जा रहा है। तकनीकी संरचना की भी निरंतर आधार पर समीक्षा की जा रही है और यूपीआई के साथ अंतरसंचालनीयता, दशमलव भुगतान को संसाधित करने की क्षमता आदि जैसी कई कार्यात्मकताएं शुरू की गई हैं। 16 मार्च, 2026 तक, रिटेल सीबीडीसी पायलट में 19 बैंक भाग ले रहे हैं, और दिसंबर 2022 में इसकी स्थापना के बाद से एक करोड़ उपयोगकर्ता शामिल हुए हैं। वर्तमान में, थोक सीबीडीसी पायलट में 16 प्रतिभागी हैं, जिसमें बैंक और गैर-बैंक शामिल हैं।

(ग) और (घ): सीबीडीसी के सीमा-पार भाग के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंकों और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ चर्चा कर रहा है, और रियाल्टो (सिंगापुर केंद्र) और एपर्टा (हांगकांग केंद्र) जैसी बहुपक्षीय परियोजनाओं में शामिल हो गया है। आरबीआई सिंगापुर केंद्र के नेतृत्व में प्रोजेक्ट मंडला के चरण 2 में भी भागीदार बन गया है। सीबीडीसी में सीमा पार लेनदेन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने की क्षमता है। सीबीडीसी अंतरराष्ट्रीय प्रेषण की लागत को सुव्यवस्थित करके, कई मध्यस्थों से जुड़े जोखिमों को कम करके, तेजी से निपटान समय के माध्यम से दक्षता बढ़ाकर, 24x7 उपलब्धता और भुगतान की स्थिति में अधिक पारदर्शिता प्रदान करके लाभ प्रदान कर सकता है।

*****